तत्काल निर्गम

विश्व बैंक

संपर्क: *दिल्ली में:* गीजांजलि चोपड़ा (91 11) 2461-7241
ईमेल: gchopra@worldbank.org
वाशिंगटन में : करीना मानेसहा (202) 473-1729
ईमेल : kmanasseh@worldbank.org

विश्व बैंक ने तमिलनाडु में स्वास्थ्य प्रणालियों में सुधार को सहायता प्रदान की।

इस परियोजना से एक दक्षिण भारतीय राज्य लाभान्वित होगा

वाशिंगटन, डीसी, 16 दिसंबर, 2004 — आज विश्व बैंक ने भारत के तमिलनाडु राज्य की सार्वजनिक एवं निजी, दोनों स्वास्थ्य प्रणालियों की कारगरता में सुधार लाने के लिए सहायता हेतु 110.83 मिलियन अमेरिकी डालर का ऋण अनुमोदित किया है।

तमिलनाडु स्वास्थ्य प्रणाली परियोजना में विश्व बैंक की भागीदारी से इस राज्य के स्वास्थ्य क्षेत्र की कार्यविधियों में नए तरीकों की शुरुआत करने में सहायता मिलेगी जैसे निजी क्षेत्र के साथ सहयोग को प्रोत्साहन देना, गुणवत्ता आश्वासन तंत्रों को अपनाना तथा असंक्रामक रोगों के बढ़ते हुए बोझ की समस्या का निवारण करना। हालांकि तमिलनाडु में स्वास्थ्य प्रणाली अपनी जनसंख्या की बुनियादी स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने में काफी कारगर रही है, फिर भी यह आशा है कि इस परियोजना के लक्ष्यों से क्रांतिक सुधारों का प्रभाव प्रदर्शित होगा।

तमिलनाडु ने टीकाकरण जैसी निवारक सेवाओं को सफलतापूर्वक प्रदान किया है जिसका परिणामस्वरूप समय के दौरान इसकी नवजात शिशु मृत्यु दर तथा पांच वर्ष से कम आयु में मृत्यु दर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। 1992 से 1999 तक नवजात शिशु मृत्यु दर 71 से घटकर 48 प्रति हजार हो गई है तथा पांच वर्ष से कम आयु में मृत्यु दर 97 से घटकर 73 प्रति हजार हो गई है। बहरहाल, ये दरें अभी भी श्रीलंका तथा पड़ोसी राज्य केरल से अत्यधिक उच्चतर हैं जहां, उदाहरणार्थ, क्रमशः 12 और 16 की नवजात शिशु मृत्यु दर हैं।

विश्व बैंक में वरिष्ठ सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ **प्रीति कुडेश्यिा** का कहना है, *"तमिलनाडु ने पिछले दशकों के दौरान स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करने तथा स्वास्थ्य देखरेख सेवओं तक पहुंच को बढ़ाने के क्षेत्रों में उललेखनीय प्रगति की है। तथापि, यह अभी निश्चल नवजात शिशु एवं मातृत्व मृत्यु दरें, असंक्रामक रोगों के बढ़ते हुए बोझ, देखरेख की खराब गुणवत्ता, समभाव संबंधी मुद्दों तथा राज्य में स्वास्थ्य वित्त व्यवस्था के कम स्तर जैसे प्रमुख चुनौतियों का सामना कर रहा है।"*

इन चुनौतियों का सामना करने के लिए तमिलनाडु सरकार ने 2003 में एक स्वास्थ्य नीति तैयार की थी। इस नीति में अगले दो दशकों के दौरान निम्न–आय समुदायों तथा परिवारों के स्वास्थ्य पर विशेष जोर देते हुए आम जनता के स्वास्थ्य की स्थिति को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह परियोजना इस नीति के क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करेगी।

इस परियोजना के चार घटक हैं :

- स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच तथा उनके उपयोग को बढ़ाना, विशेषकर गरीब, सुविधा से वंचित तथा आदिवासी समूह;

- स्वास्थ्य संबंधी मुख्य चुनौतियों विशिष्ट रूप से असंक्रामक रोगों तथा यातायात दुर्घटनाओं का निवारण करने के लिए कारगर मध्यस्थता विकसित तथा पायलट परीक्षण करना।;

- सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों के सुदृढ़ पूर्वावलोकन के माध्यम से स्वास्थ्य परिणाम, पहुंच और सेवा प्रदान किए जाने की गुणवत्ता में सुधार करना, और गैर–सरकारी क्षेत्र की अधिक भागीदारी।;
- मूलतः ज़िला और उप–जिला स्तरों पर सार्वजनिक क्षेत्र की अस्पताल सेवाओं की कारगरता और कुशलता में सुधार करना।

इस परियोजना की मंशा है कि इसके सभी घटकों के क्रियान्वयन में सार्वजनिक–निजी भागीदादियों को समर्थन प्रदान करके विकास को बल प्रदान किया जाए। पूरे राज्य में असंक्रामक रोगों के लिए जोखिम कारक रोकथाम को क्रियान्वित किया जाएगा जबकि हाइपर टेंशन तथा सर्विकल कैंसर की रोकथाम और प्रबंधन की पायलट नीतियों की कारगरता का चुनिंदा ज़िलों में कड़ा परीक्षण किया जाएगा। यह परियोजना नवजात शिशु तथा मातृत्व मृत्यु दरों में कमी लाने के लिए एक आक्रामक नीति के जरिए व्यापक आपातकालीन प्रसूति और प्रसूति उपरांत देखरेख भी सुनिश्चित करेगी और इसमें दूरस्थ या आदिवासी व्यक्तियों की आबादी वाले क्षेत्रों को पहले सहायता प्राप्त होगी। अवसंरचना सुधार तथा देखरेख की उन्नत गुणवत्ता को साथ–साथ चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित किया जाएगा।

इस परियोजना से भारत देश के अधिक व्यापक नीतिगत उद्देश्य जैसे शासन में सुधार, सेवाओं तक पहुंच में विस्तार तथा उनकी कारगरता एवं गुणवत्ता का उन्नयन तथा सामुदायिक भागीदारी संवर्धन एवं सशक्तीकरण के लिए योगदान मिलने की आशा है। विश्व बैंक के रियायती ऋण निकाय अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (IDA) के ऋण में 0.75 प्रतिशत सेवा प्रभार, 10 वर्ष की छूट अवधि तथा 35 वर्ष की परिपक्वता शामिल है।

कृपया भारत में विश्व बैंक की गतिविधियों की अधिक जानकारी के लिए निम्न एड्रेस पर संपर्क करें :
http://www.worldbank.org/in